Likelyhood of Good Kharif Crops

1319. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether this year also there is likely to be good kharif crops;

(b) the percentage of land area entirely dependent on monsoon for kharif crops; and

(c) whether there is any proposal to cover more area under irrigation as compared to last year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir. As per present rainfall and weather situation, a nother good kharif crop is anticipated this year.

(b) As per Land Use Statistics, about 76.6 percent of the gross sown area under kharif crops depends on rainfall.

(c) During the year 1995-96, it is proposed to create an additional irrigation potential of 23.47 lakhs hectare as compared to 21.32 lakh hectare anticipated during 1994-95.

ब्रिटिश काउंसिल की मदद से अंग्रेजी के नये पाठ्यक्रम को प्रारंभ करना

1320. **श्री जनेश्वर मिश्रः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्रिटिश काउंसिल की मदद से अंग्रेजी के एक नये पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और इसके लिये 55 भारतीय शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड भेजा जा चुका है;

(ख) ब्रिटिश काउंसिल द्वारा इस कार्य के लिये कितनी धनराशि दी जा रही है तथा उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) इस तरह के प्रयोग सरकार कहां-कहां तथा कितने स्कूलों में करने का विचार रखती है; और

(घ) इस संबंध में तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री) (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में माध्यमिक कक्षा स्तर पर अंग्रेजी पाठ्यक्रम "क" की पाठ्यचर्या को पुनरीक्षित तथा संशोधित करने और माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण स्तर में सुधार करने की दृष्टि से ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ०डी०ए०), यूनाइटेड किंगडम, तथा ब्रिटिश काउनसिल डिवीजन के सहयोग से 1989 में एक परियोजना आरंभ की थी। वर्ष 1989—1991 की अवधि के दौरान, इस परियोजना के अंतर्गत कुल 55 शिक्षक तथा कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजे गए थे। बोर्ड ने सूचित किया है कि वर्ष 1988—1995 की अवधि के दौरान ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्रदत्त वित्त पोषण लगभग 879,430 पौण्ड होने का अनुमान है। ब्रिटिश काउंसिल डिवीजन द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत आयोजित किए गए विभिन्न स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए निधियां संवितरित की जाती हैं। इस परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध तथा कक्षा IX-X स्तर पर अंग्रेजी पाठ्यक्रम "क" प्रदान करने वाले सभी विद्यालयों को शामिल कर लिया गया है। ऐसे विद्यालयों की कुल संख्या 2556 है।

Operations of NSC in Andhra Pradesh

1321. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether National Seeds Corporation has extensive operations in Andhra Pradesh;

(b) if so, the extent of its operations;

(c) whether it is a fact that very frequently farmers are put to huge losses by National Seeds Corporation;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) whether National Seeds Corproation will consider this business strategy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) Yes, Sir. Details of operations of National Seeds Corporation (NSC) Limited, a public sector undertaking under

the adminsitrative control of Ministry of Agriculture are given below:

(i) NSC has its regional office located at Lallaguda, Secunderabad (A.P.) in addition to four area offices located at Lallaguda, Warrangal, Guntur and Kurnool. Main operations of NSC in the State are production of breeder seed, foundation seed, certified seed, processing, packing, storage and sale of certified seeds through its sale counters and dealership network.

(ii) The Corporation has also a 200 hectares farm located at Nandikotkur, District-Kurnool. The farm is producing breeder seed and foundation seed of a wide range of crop varieties.

(iii) The Corporation has a Quality Control Laboratory in Secunderabad for testing samples received from its offices in Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala and Madhya Pradesh.

(c) No, Sir.

(d) & (c) In view of the position indicated above, the question do not arise.

Shifting of Government and PSU Offices

1322. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state;

(a) whether Government had identifed some of the Government offices and the Public Sector Units to be shifted out of Delhi long time back;

(b) if so, how many of the identified offices have actually been shifted out of Delhi and by when will the remaining offices/units be shifted;

(c) whether there is any proposal to ideitify more number of Government offices and public sector units for shifting out of Delhi; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) Three Government Offices and four Public Sector Units have been actually shifted out of Delhi. The actual shifting of Government offices/public Sector Units depends upon a number of determining factors like availability of land, construction of building etc. In view of this, no time frame can be set for actual shifting of the remaining Government offices/Public Sector Units.

(c) There is no such proposal.

(d) Does not arise.

समारकों से चोरी होने की घटनायें

1323. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत स्मारकों तथा अन्य स्थानों से चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी घटनाएं हुई और चोरी किस-किस तरह की थी तथा कौन-कौन की वस्तुएं चोरी हुई; और

(क) इन चोरियों में अंतर्ग्रस्त पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही बरतने के दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा 30 जून, 1995 तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग): पिछले दो वर्षों में चोरी के 14 मामले पकड़े गए जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 5 कर्मचारियों का शामिल होना पाया गया है। अनुपत्र के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। **(देखिये** परिशिष्ट 174, अनुपत्र सं छट]